2 संजय शाह ने केंद्रीय राज्यमंत्री को सौंपा पत्र

5 समान महत्व देने वाले नेता हैं अखिलेश यादव

6 ट्रंप और मस्क विवाद का कारण मोदी तो नहीं?

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 08 | प्रति सोमवार, 30 जून 2025 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

प्रदेश बीजेपी के नये अध्यक्ष की तैयारी अंतिम चरण में, वीडी शर्मा के कार्यकाल पर उठे सवाल

कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा या हेमंत खंडेलवाल को मिल सकती है जिम्मेदारी?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की सुगबुगाहट अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। पार्टी के अंदरखाने से मिल रहे संकेतों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अगले एक दो दिन में हो सकती है। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा का कार्यकाल बीते कई महीनों से एक्सटेंशन पर चल रहा था, लेकिन अब संगठन में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि वीडी शर्मा का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा है।

संगठनात्मक दृष्टि से उनके कार्यकाल में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन, जनसंवाद या उपलब्धि नहीं रही जिसे भाजपा अपनी सफलता के तौर पर प्रस्तुत कर सके। विधानसभा चुनाव में मिली जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति और कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान का परिणाम माना गया। संगठन की भूमिका सीमित ही रही। यही वजह है कि वीडी शर्मा के कार्यकाल का आंकलन निराशाजनक माना जा रहा है।

लगातार विवादों में रहे शर्मा

वीडी शर्मा के नेतृत्व पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि उनका कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। सत्ता के गलियारों से लेकर संगठन और जमीनी कार्यकर्ताओं तक में उनके खिलाफ नाराजगी का भाव देखा गया। कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके व्यवहार और निर्णयों को लेकर सार्वजनिक व निजी तौर पर असंतोष जाहिर किया। (शेष पेज 2 पर)

कमलनाथ की विरासत पर भाजपा सवार, 2028 में कांग्रेस की राह, अनुभव और युवा तालमेल पर निर्भर

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में बदलाव की आहटें अभी से सुनाई दे रही हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में भले ही सत्ता भाजपा के हाथ में है, लेकिन सूबे की राजनीतिक फिजा में अब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नीतियों और निर्णयों की गूंज बरकरार है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। (शेष पेज 5 पर)

सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास के नए पथ पर अग्रसर हो रहा छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सौगातों की झड़ी, हर वर्ग को दी राहत, युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने की बड़ी योजना

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लगातार प्रदेशवासियों को सौगातें देने में जुटे हुए हैं। उनके कामकाज और घोषणाओं में साफ झलकता है कि जनता की खुशहाली ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे गांव-गांव, शहर-शहर दौरे कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और अफसरों को त्वरित समाधान के निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राजधानी रायपुर के विशाल मंच से कहा, यह सरकार गरीबों, बहनों-बेटियों, किसानों और युवाओं की है। हर वर्ग को उसका हक दिलाना हमारा संकल्प है। प्रदेश का समग्र विकास और सामाजिक समरसता हमारी प्राथमिकता रहेगी।

बहनों-बेटियों को मिली सौगातें

विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की घोषणा की गई। इसके अलावा महिला समूहों को बिना ब्याज ऋण देने की योजना को और अधिक व्यापक बनाया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। (शेष पेज 3 पर)

क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लापरवाही और विमानन विभाग के अधिकारियों के कारण क्रैश हुआ था अगस्ता हैलीकॉप्टर?

-विजया पाठक

अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान और केदारनाथ में हुए हैलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना ने देश की विमानन सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह प्रश्न आज उठाना इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि इस घटना ने छत्तीसगढ़ में मई 2022 में हुए शासकीय हैलीकॉप्टर अगस्ता-109 क्रैश की घटना को दोबारा जीवित कर दिया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुई इस हैलीकॉप्टर क्रैश की घटना ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरी राज्य सरकार की विश्वसनीयता को सकते में डाल दिया।

विगत विधानसभा चुनाव से पहले डीजीसीए द्वारा इस पूरे मामले की बारीकी से जांचकर आरोपियों को सजा देने के लिए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंप दी थी। लेकिन शासकीय कार्य में ढीला रवैया रखने वाले बघेल और उनकी चंडाल चौकड़ी ने इस पूरे मामले को दबा दिया और न ही दोषियों को सजा दी गई और ना ही डीजीसीए की रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया गया। (शेष पेज 3 पर)

क्या वीडी शर्मा के विवादों, नाराजगी और संगठनात्मक कमजोरी के बीच पार्टी नए अध्यक्ष के जरिए नई ऊर्जा भरना चाहती है?

(पेज 1 का शेष)

पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शर्मा ने संगठन को मजबूत करने के बजाय गुटबाजी और व्यक्तिगत लॉबी पर ज्यादा ध्यान दिया। साथ ही चुनावों में पैसे कमाना, टिकटों की बिक्री करना जैसे काम करते रहे। उन्होंने कहा, "भाजपा जैसा अनुशासित दल व्यक्ति आधारित नहीं, संगठन आधारित रहता है। लेकिन यहां संगठन कमजोर और व्यक्ति मजबूत नजर आया।"

देवड़ा, शाह प्रकरण से भी बढ़ी नाराजगी

प्रदेश भाजपा में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विजय शाह को लेकर भी शर्मा की भूमिका सवालों के घेरे में रही। मंदसौर में एमडी ड्रग्स प्रकरण के उजागर होने के बाद, जिसमे लाखों की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई थी, उस पर कार्यवाही को लेकर पार्टी में असंतोष है। वहीं सेना का अपमान करने वाला बयान देकर देवड़ा और शाह ने पार्टी की किरकिरी कराई, लेकिन इसके बावजूद वीडी शर्मा ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय नेतृत्व इस मामले को लेकर नाराज है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, सेना का अपमान हो और भाजपा अध्यक्ष चुप रहे, यह विचारधारा के खिलाफ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं वीडी शर्मा ने इन दोनों नेताओं से किसी प्रकार की सांठगांठ तो नहीं कर ली।

कौन बन सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष?

भाजपा में नए अध्यक्ष को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व इस बार ऐसा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहता है, जो 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी पार्टी को मजबूत कर सके। संगठन में चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों के संगठन को मजबूत करने के एजेंडे पर है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में भी बदलाव होगा। 2028 का मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव मुश्किलों भरा होने वाला है। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे संगठन में ऐसे नेता की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। और पार्टी को और मजबूत करने में सफलता हासिल करे। सूत्रों के अनुसार जो नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं, उनमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, अर्चना चिटनिस, लाल सिंह आर्य, माया सिंह के नामों को लेकर सरगर्मी तेज है।

केंद्रीय नेतृत्व का फोकस 2028 और 2029 पर

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 2029 तक का रोडमैप तैयार कर रहा है। उनका मानना है कि मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए तेजतर्रार और जनाधार वाले नेता की जरूरत है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश सरकार में चेहरे को लेकर बदलाव किया गया और अब संगठन में भी बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।

शर्मा का क्या होगा?

वीडी शर्मा को लेकर माना जा रहा है कि संगठन उन्हें दिल्ली बुलाकर कोई जिम्मेदारी दे सकता है। हालांकि उनकी उपलब्धियों का ग्राफ बेहद कमजोर रहा है। पार्टी के कई जिलों में अभी भी संगठन के ढांचे अधूरे पड़े हैं। प्रदेश के बड़े आंदोलनात्मक विषयों पर भी संगठन की सक्रियता नगण्य रही। कई जिलाध्यक्षों ने बीते दिनों शिकायत की थी कि अध्यक्ष उनसे मिलना तो दूर, बात भी नहीं करते।

संगठन में बदलाव का असर

प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव का असर न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर होगा, बल्कि आगामी चुनावों की रणनीति पर भी दिखेगा। संगठन मजबूत होगा तो सरकार का कामकाज भी जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, मुख्यमंत्री अकेले विकास कार्य नहीं कर सकते। मजबूत संगठन ही सरकार की रीढ़ होता है। एक राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मुझे उम्मीद है कि मध्यप्रदेश भाजपा के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडी शर्मा के कार्यकाल में विवादों, नाराजगी और संगठनात्मक कमजोरी के बीच पार्टी अब नए अध्यक्ष के जरिए नई ऊर्जा भरना चाहती है। आने वाला समय बताएगा कि भाजपा नेतृत्व किस चेहरे पर भरोसा जताता है, लेकिन इतना तय है कि बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है।

05 साल में शर्मा की संपति 04 गुना बढ़ी

वीडी शर्मा की बीते 05 साल में संपत्ति 04 गुना से ज्यादा बढ़ी है। 05 साल पहले वीडी शर्मा की संपत्ति करीब 68 लाख और पत्नी की कुल चल-अचल संपत्ति को मिलकर करीबन 01 करोड़ रुपए थी, जिसमें अब 04 गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। वीडी शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन के साथ संपत्ति का ब्यौरा पेश किया था। उस समय वीडी शर्मा की नगदी, बैंक बैलेंस सहित कुल चल संपत्ति 21 लाख 37 हजार 581 रुपए और पत्नी स्तुति शर्मा की 17 लाख 49 हजार 240 रुपए बताई थी। निश्चित ही अब समय आ गया है कि पार्टी हाईकमान जल्द से जल्द प्रदेश में अध्यक्ष का चेहरा बदले। नहीं तो बहुत देर हो जायेगी। क्योंकि पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर वीडी शर्मा का काफी विरोध होने लगा है। अंदर ही अंदर कई नेताओं ने गुट पनपने लगे हैं जो आने वाले समय में नुकसान दायक साबित होंगे।

संगठन को खड़ा करने में नाकाम रहे वीडी शर्मा

वीडी शर्मा की नाकामियों में एक इजाफा यह भी है की उन्होंने प्रदेश में संगठन को खड़ा करने में काफी कोताही बरती है। अपने कार्यकाल में करीब 11 माह बाद तो उन्होंने जिला स्तर पर संगठन खड़ा किया था, जिससे जिला स्तर पर कई गुट तैयार हो गये। कह सकते हैं कि उन्होंने संगठन के कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई बल्कि अपनी नेतागीरी जमाने में लगे रहें। आज भी वह खुद के अलावा किसी को तवज्जो ही नहीं देते हैं। हाल ही में प्रदेश स्तर पर संगठन के पद भरे गये हैं उसमें भी काफी विरोधाभास देखने में मिला है। वीडी शर्मा ने अपने चहेतों को ही इन पदों पर बिठाया है। यहां तक सत्ता के लोगों की पसंद को भी तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा इनके चरित्र को लेकर भी समय-समय पर प्रश्नचिंह लगते रहे हैं।

राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हुए शामिल

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है, उतना ही बड़ा उत्सव छत्तीसगढ़ के लिए भी है। साय ने कहा कि भगवान जगन्नाथ किसानों के रक्षक हैं। उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, धान की बालियों में दूध भरता है और किसानों के घरों में समृद्धि आती है। मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ में भरपूर फसल हो। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से मेरी विनती है कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की ओर अग्रसर करें। राजधानी रायपुर

के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में पुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर यह पुरानी परंपरा निभाई जाती है। मुख्यमंत्री साय ने छेरापहरा की रस्म पूरी करते हुए सोने की झाड़ू से मार्ग बुहारकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को रथ तक ले जाकर विराजित किया।राज्यपाल डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर 'छेरा-पहरा' की रस्म निभाई। रथ यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से रथ तक लाया गया और मार्ग को सोने की झाड़ू से स्वच्छ किया गया। इस परंपरा को छेरापहरा कहा जाता है। रथ यात्रा के लिए भारत में ओडिशा राज्य प्रसिद्ध है। ओडिशा का पड़ोसी राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी इस उत्सव का व्यापक प्रभाव है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की विशेष विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी के अनुसार उत्कल संस्कृति और दक्षिण कोसल की संस्कृति के बीच यह एक अटूट साझेदारी का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान छत्तीसगढ़ का शिवरीनारायण तीर्थ है, जहां से वे जगन्नाथ पुरी में स्थापित हुए। शिवरीनारायण में ही त्रेता युग में प्रभु श्रीराम ने माता शबरी के प्रेमपूर्वक अर्पित मीठे बेर ग्रहण किए थे। यहां वर्तमान में नर-नारायण का भव्य मंदिर स्थापित है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा, धर्मलाल कौशिक सहित अन्य गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

पूर्व विधायक संजय शाह ने केंद्रीय राज्यमंत्री को सौंपा पत्र

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। पूर्व विधायक संजय शाह ने टिमरनी रहटगांव तहसील क्षेत्र के परिसीमन को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने क्षेत्र की जनभावनाओं को समझते हुए केंद्रीय जनजाति कार्य राज्यमंत्री एवं बैतूल-हरदा के सांसद दुर्गादास उइके को पत्र लिखकर उक्त विषय में अवगत कराया। पूर्व विधायक संजय शाह द्वारा लिखे गए पत्र में बताया गया है कि ग्राम सौताड़ा, निमाचा, भायली, भादूगांव, सामरधा, उन्द्राकच्छ, उस्कल्ली, अम्बेरीखेड़ा, बैहराखेड़ी, धौलपुर कला, लहाड़पुर, गुरारखेड़ा, गुरंजघाट, पिपल्या माफी भौगोलिक रूप से टिमरनी तहसील के अत्यंत समीप स्थित हैं। इसके बावजूद इन गांवों को प्रशासनिक कार्यों के लिए रहटगांव तहसील जाना पड़ता है, जो कि 15 से 20 किलोमीटर दूर है, जबकि टिमरनी मात्र 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व विधायक संजय शाह ने पत्र में उल्लेख किया कि विशेष रूप से वर्षा ऋतु में ग्रामीणों को रहटगांव तहसील तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे शासकीय कार्यों में विलंब एवं असुविधा उत्पन्न होती है। इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने मांग की है कि जनसुविधा की दृष्टि से इन ग्रामों को टिमरनी तहसील में शामिल किया जाए।पारिवारिक कारणों से संजय शाह स्वयं उपस्थित नहीं हो सके किंतु यह पत्र टिमरनी मंडल अध्यक्ष अतुल बारंगे, पार्षद सुनील दुबे द्वारा केंद्रीय राज्यमंत्री को सौंपा गया। इस अवसर पर पार्षद गुलशन चौरसिया, अक्षय शांडिल्य सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन शीघ्र ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा, जिससे उन्हें राहत मिल सकेगी।

सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकास के नए पथ पर अग्रसर हो रहा छत्तीसगढ़

(पेज 1 का शेष)

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों-बेटियों का आत्मनिर्भर होना पूरे समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। "हर पंचायत में महिलाओं की आय बढ़े, यह मेरी जिम्मेदारी है," उन्होंने अपने दौरे के दौरान कहा।

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है मुख्य मकसद

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को विस्तार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत युवाओं को बैंक ऋण में गारंटी, प्रशिक्षण, मार्केट लिंक और तकनीकी मदद एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, लेकिन सरकार ऐसा माहौल जरूर बना सकती है जिसमें हर युवा अपने हुनर के मुताबिक रोजगार कर सके। उन्होंने आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों के उन्नयन, कृषि आधारित उद्योगों में रोजगार सृजन, लघु उद्योगों के विकास, और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है।

किसानों को राहत, कृषि यंत्र और बिजली बिल पर फैसले

प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, सिंचाई पंपों की बिजली दरों में कमी और धान खरीदी भुगतान को लेकर समयबद्ध प्रक्रिया का आदेश जारी किया गया है। विष्णुदेव साय ने कहा कि किसान आत्मनिर्भर होगा तो गांव समृद्ध होंगे और छत्तीसगढ़ का अर्थतंत्र मजबूत होगा।

गरीबों के घर तक पहुंचेगा विकास

छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण कार्य में गति लाई गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले दो वर्षों में प्रदेश में 'कच्चा मकान' शब्द सुनाई न दे, यह उनका सपना है। साथ ही, राशन कार्ड धारकों को समय पर खाद्यान्न वितरण के लिए पीडीएस की मॉनिटरिंग और गोदामों की ऑनलाइन निगरानी को और प्रभावी बनाया गया है।

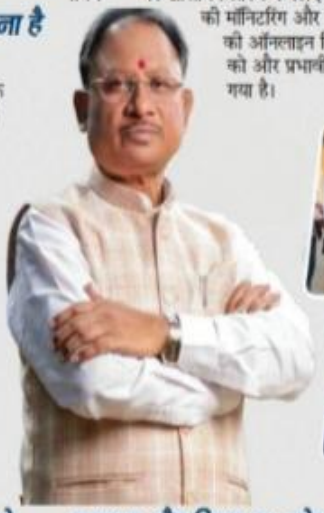

स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इससे दूरस्थ आदिवासी अंचलों में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के उन्नयन, स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंटेंट, लैब और लाइब्रेरी के विस्तार पर कार्ययोजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री का कहना है, सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाएंगे कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर न हो।

विकास में युवाओं की भूमिका

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट मानना है कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले भी बनें। इसीलिए उनकी सरकार कौशल विकास, स्टार्टअप नीति, ऑनलाइन मार्केटिंग स्किल और स्वरोजगार को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है। उसकी तकलीफ मेरी जिम्मेदारी है। सरकार का काम ही है लोगों के जीवन में बदलाव लाना।

लगातार हो रहे निर्णय

बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिये हैं। इनमें गोठानों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि, पशुधलन के लिए नई योजनाएं, वृक्षारोपण महाभियान, और रायपुर समेत अन्य नगर निगमों में सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान शामिल हैं। वे खुद भी योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अफसरों की बैठक लेकर हर योजना की प्रगति की समीक्षा करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है।

जनता से सीधा जुड़ाव

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सबसे बड़ा राजनीतिक प्लस पॉइंट है जनता से उनका सीधा जुड़ाव। वे अपने सरल, सहज व्यवहार से लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। सरगुजा दौरे के दौरान जब एक वृद्ध महिला ने कहा कि उसका राशन कार्ड काट दिया गया है तो मुख्यमंत्री ने तुरंत कलेक्टर को बुलाकर समस्या का समाधान करवाया। इसी तरह बिलासपुर प्रवास के दौरान उन्होंने युवक के स्वरोजगार ऋण आवेदन को स्वीकृत करवाया। मुख्यमंत्री का मानना है कि छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। उन्होंने अफसरों से कहा है कि 'फाइलों पर नहीं, जमीन पर काम दिखना चाहिए।' उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में युवाओं के लिए एक बड़ी रोजगार नीति लाई जाएगी जिसमें सरकारी भर्तियों के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी विशेष प्रावधान होंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अल्प अवधि में ही अपनी कार्यशैली से स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए पद नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का सुख महत्वपूर्ण है। बहनों-बेटियों से लेकर युवाओं तक, हर वर्ग को सौगातें देने का उनका प्रवास लगातार जारी है। उनकी योजनाएं अगर समयबद्ध ढंग से जमीन पर उतरती हैं, तो छत्तीसगढ़ निश्चित ही विकास के नए पथ पर अग्रसर होगा।

क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लापरवाही और विमानन विभाग के अधिकारियों के कारण क्रैश हुआ था अगस्ता हैलीकॉप्टर?

(पेज 1 का शेष)

सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले पर भूपेश बघेल ने जानबूझकर पर्दा डालने का प्रयास किया था क्योंकि इस हैलीकॉप्टर क्रैश से पहले उन्होंने इसी हैलीकॉप्टर के मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपये चट कर लिये। यही इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार का विमानन विभाग कठघरे में खड़ा हो गया और सड़क से लेकर विधानसभा तक विपक्ष ने कई बार इस विषय को उठाया लेकिन बघेल सरकार ने कभी इस पर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा।

घटना के बाद डीजीसीए ने बनाई थी जांच कमेटी

जानकारी के अनुसार जब मई 2022 में यह घटना हुई तो उसके बाद डीजीसीए ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस घटना में हैलीकॉप्टर के अंदर बैठे दोनों ही पायलट की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद घटना की सही जानकारी पाने के लिए डीजीसीए ने यह हथकंडा अपनाया और हैलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की मदद से पूरी घटना की छानबीन की।

आगे भी हो सकती है अगस्ता जैसी घटनाएं

डीजीसीए के अनुसार लंबे वक्त के बाद भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंवेस्टीगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट पर अमल ना करने से, हवाई दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। यह रिपोर्ट नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर दबाये-छिपाये जाने का मामला संगीन ही नहीं बल्कि आपराधिक दायरे में बताया जा रहा है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार के विमानन विभाग की कथनी और करनी पर सवालियां निशान उठा रही है। अगर सरकार का यही रवैया रहा और इस तरह की घटनाओं को सीरियस नहीं लिया गया। वह समय दूर नहीं जब राज्य में अगस्ता जैसी और भी घटनाएं होने की अंदेशा है। 136 पेज वाली इस जांच रिपोर्ट में हैलीकॉप्टर क्रैश होने के कई कारणों के साथ ही एविएशन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालियां निशान लगाया गया है।

नहीं हुआ था नियमानुसार मेंटेनेंस

किसी भी हैलीकॉप्टर की यदि उसकी क्षमता से अधिक उड़ान भरी जाती है तो निश्चित ही उसका रखरखाव भी उच्च स्तर का होना चाहिए। लेकिन तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया और हैलीकॉप्टर को मापदंडों के अनुसार मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसके कारण हैलीकॉप्टर क्रैश जैसी घटना हुई।

भूपेश सरकार ने छुपाए थे कई महत्वपूर्ण तथ्य

रिपोर्ट में कहा है कि दिसंबर 2021 में संगठन के फिक्स्ड विंग विमान से जुड़ी घटना के बारे में चालक दल और रखरखाव कर्मियों ने तथ्यों को छिपाया गया था। संगठन में उड़ान सुरक्षा के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। संगठन में सुरक्षा संबंधी आंतरिक ऑडिट बिना उचित महत्व दिए किए जा रहे हैं। पिछले 05 वर्षों के दौरान इनमें से किसी भी ऑडिट में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। डीजीसीए सीएआर सेक्शन 5, सीरीज एफ, भाग 1 के अनुसार सीएआर में दी गई आवश्यकताएं अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं, कार्गो सेवाओं, गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं में लगे सभी ऑपरेटरों पर लागू होती हैं।

जांच समिति को नहीं मिला था हैलीकॉप्टर का मेंटेनेंस रिकॉर्ड

रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि विभाग के पास अपने एओपी के तहत केवल 02 विमान हैं, जिनमें से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिक्स्ड विंग वी 200 विमान दिसंबर 2021 में हुई घटना के बाद से लंबे समय तक ग्राउंडेड रहा, जो सुरक्षित विमान संचालन के लिए जिम्मेदार कर्मियों द्वारा कार्यों की खराब पूर्ति को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि प्रबंधन द्वारा गतिविधियों की देखरेख पूरी लगन से नहीं की जाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की मूल वजह 'टेलरोटर' को बताया जा रहा है, समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी इसे बदला नहीं गया था। जबकि हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस रिकॉर्ड एविएशन विभाग से ही नदारद पाया गया।

इंटेलियन कंपनी ने किया था हैलीकॉप्टर का निर्माण

अगस्ता वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर इटेलयन कंपनी का बनाया हुआ था। ये हैलीकॉप्टर 109 पॉवर एलिट मॉडल का था। खास बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में सरकारी हैलीकॉप्टर मैना के क्रैश होने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड को 14 जुलाई 2007 को खरीदा गया था। 15 साल में प्रदेश सरकार का यह दूसरा हैलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ। इससे पहले राज्य सरकार का यूरोकॉप्टर मैना बालाघाट जिले के सरटेकरी व डोंडहा पथरा जंगल में क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट सहित चार लोगों की मौत हो गई थी।

सम्पादकीय

जनसंख्या गणना देश के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली प्रक्रिया

जनसंख्या गणना किसी भी देश की नियोजन, नीति निर्माण और संसाधन वितरण की आधारशिला होती है। भारत में हर दस वर्ष बाद जनगणना की परंपरा चली आ रही है। स्वतंत्रता के बाद 1951 से निरंतर यह प्रक्रिया सम्पन्न होती रही है और अब देश 2025-26 में अपनी 16वीं जनगणना की तैयारी कर रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की गणना स्थगित हो गई थी, जिसके चलते यह गणना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ऐसे में जनगणना के आंकड़े केवल संख्या तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इससे सरकार को नीतियां बनाने, योजनाएं तैयार करने और बजट आवंटन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

जनगणना के आंकड़ों के आधार पर केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण व आधारभूत संरचना की योजनाएं बनाती हैं। जनसंख्या घनत्व और संरचना जानने से राज्यों, जिलों, गांवों व शहरों को संसाधनों का न्यायसंगत वितरण होता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्गों की संख्या का सही आकलन आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन की प्रक्रिया में सहायक होता है। शिक्षाविद, शोधकर्ता, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री इन आंकड़ों का उपयोग अपने शोध और नीतिगत सुझावों के लिए करते हैं। हाल की महामारी ने दिखाया कि अद्यतन व डिजिटल जनगणना आंकड़े स्वास्थ्य आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने में सहायक हो सकते हैं।

पहली बार डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह होगा। नागरिक स्वयं भी मोबाइल एप या वेबपोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकेंगे। डिजिटल के साथ ही परंपरागत घर-घर जाकर गणनाकार्य भी किया जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति छूट न जाए। एनपीआर का अद्यतन भी इसी के साथ किया जाएगा, जिससे प्रवासन, नागरिकता और पहचान से जुड़े आंकड़े भी इकट्ठा होंगे। लिंगानुपात, महिला साक्षरता, महिला-पुरुष रोजगार दर पर विशेष आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। ग्रामीण से शहरी प्रवासन, स्लम क्षेत्रों की स्थिति व शहरी विस्तार का डाटा योजनाकारों को मिलेगा। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में जनगणना कराना आसान कार्य नहीं है। डिजिटल गणना में साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, इंटरनेट साक्षरता जैसी चुनौतियां हैं। साथ ही जनसंख्या की विशालता, प्रवासी मजदूरों की लगातार आवाजाही, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक कठिनाइयां भी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ समूहों में डेटा गोपनीयता को लेकर अविश्वास भी रहता है। इसलिए व्यापक जनजागरूकता अभियान की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार ने 2025-26 की जनगणना के लिए 12,000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया है। प्रशिक्षित गणनाकार, सुपरवाइजर, स्टेटिस्टिकल अफिसर और उच्च स्तरीय डिजिटल मॉनिटरिंग से इसे प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनगणना कार्यालय ने सॉफ्टवेयर, एप और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्नत किया है। राज्य सरकारों को भी समन्वय में लगाया गया है। जनगणना केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि यह देश के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक न्याय, समानता, अवसर और विकास की कुंजी है। 2025-26 की यह गणना डिजिटल बदलाव का प्रतीक भी होगी। यदि इसे पारदर्शिता, सुरक्षा और समावेशी दृष्टिकोण के साथ संपन्न किया गया, तो भारत के विकास की रफ्तार को यह नयी दिशा देगी। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसमें सहयोग कर ईमानदारी से अपनी जानकारी दे, क्योंकि सही आंकड़े ही सशक्त भारत के निर्माण की नींव रखते हैं।

सियासी गहमागहमी

मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंची अफसरों की आपसी खींचतान

मध्यप्रदेश में इन दिनों आईएएस अफसरों के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। मामला कर्मचारियों की पदोन्नति नियमावली बनाने का है, जहां वरिष्ठ अफसरों के विचार आपस में टकरा गये। सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ अफसर चाहते हैं कि पदोन्नति में वरिष्ठता को प्राथमिकता मिले, वहीं वित्त और कार्मिक विभाग के अफसर योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू कराने पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि विभागीय बैठक में एक प्रमुख सचिव ने खुलेआम दूसरे वरिष्ठ अधिकारी के प्रस्ताव को 'व्यावहारिक नहीं' कहकर खारिज कर दिया। इससे माहौल गर्मा गया और बहस इतनी बढ़ी कि बैठक स्थगित करनी पड़ी। सचिवालय गलियारों में चर्चा है कि कुछ अफसर कर्मचारियों को खुश कर सरकार की छवि सुधारना चाहते हैं तो कुछ अफसर आर्थिक भार बढ़ने के कारण नियमावली में बदलाव के खिलाफ हैं। अफसरों की यह भिड़ंत अब मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गई है। जानकार मानते हैं कि यह विवाद जितना लंबा चलेगा, कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया उतनी ही लटकती रहेगी। फिलहाल सभी को अगली बैठक का इंतजार है, जहां कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, पर अफसरों के अहं टकराव से मामला सुलझेगा या और उलझेगा, यह देखने लायक होगा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत पहुंची आलाकमान तक

मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों जीतू पटवारी को लेकर जबरदस्त खींचतान मची है। खबर है कि पटवारी के बढ़ते प्रभाव से नाराज कुछ वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली दरबार में उनकी शिकायत पहुंचा दी है। बताया जा रहा है कि इन नेताओं को पटवारी का हर मुद्दे में हस्तक्षेप करना खटक रहा है। चाहे संगठन की नियुक्तियां हों या आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति– पटवारी हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। सूत्रों की मानें तो एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि वह खुद को सीएम फेस समझने लगे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि खुद पटवारी को इस शिकायत की भनक लग चुकी है, इसलिए वे भी अपने समर्थकों के जरिये विरोधियों की खबरें दिल्ली पहुंचाने में जुट गये हैं। कोई कह रहा है कि पटवारी की महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिये नुकसानदेह है, तो कोई उन्हें आगामी चुनाव में बड़ा चेहरा मान रहा है। आलाकमान भी असमंजस में है कि आखिर मध्यप्रदेश में किसे साधे और किसे नाराज करे। फिलहाल कांग्रेस में पटवारी को लेकर खिचड़ी पक रही है, जिसका असली स्वाद आने वाले हफ्तों में सामने आएगा।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

RSS का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। RSS-BJP को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। वे बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हार्दिक मंगलकामनाएं। यह रथयात्रा हमारे समाज की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि वह सभी पर अपनी कृपा बनाए रहें। सभी नागरिक स्वस्थ, संपन्न और सुरक्षित रहें।

जय जगन्नाथ।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

सामाजिक न्याय, और विकास को समान महत्व देने वाले नेता हैं अखिलेश यादव

समता पाठक/जगत प्रवाह

अखिलेश यादव भारत के प्रसिद्ध राजनेता हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनके पिता मुलायम सिंह यादव देश के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल थे और उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी माता का नाम मालती देवी था। अखिलेश यादव का पालन-पोषण एक राजनीतिक परिवेश में हुआ, जिससे उनके व्यक्तित्व और विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। अखिलेश यादव की प्रारंभिक शिक्षा इटावा के सैफई से हुई। इसके बाद उन्होंने धौलपुर मिलिट्री स्कूल, राजस्थान से पढ़ाई की। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी गए, जहां से उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। उनका शैक्षणिक जीवन यह दर्शाता है कि वे पढ़ाई में संभीर और जागरूक विद्यार्थी थे। विदेशी शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को वैश्विक बनाया और तकनीकी व पर्यावरणीय मुद्दों पर उनकी समझ को व्यापक किया।

राजनीति में अखिलेश यादव का प्रवेश वर्ष 2000 में हुआ, जब वे कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बने। यह सीट उनके पिता मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इसके बाद उन्होंने लगातार तीन बार कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीता। संसद में रहते हुए उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, शिक्षा, और ग्रामीण विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी। उनके भाषण और सवाल विकासवादी दृष्टिकोण को उजागर करते रहे। वर्ष 2012 उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक साबित हुआ। समाजवादी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत मिला और 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे उस समय मात्र 38 वर्ष के थे, जिससे वे राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2012-2017 तक रहा। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू कीं।

उनकी प्रमुख योजनाओं में "लैपटॉप वितरण योजना" विशेष रूप से चर्चित रही, जिसके अंतर्गत 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए गए ताकि डिजिटल साक्षरता और शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा "1090 चूमेन पावरलाइन" की स्थापना, महिलाओं की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कदम था। लखनऊ मेट्रो परियोजना, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट जैसे विकास कार्य भी उनके कार्यकाल की उपलब्धियां रहीं। उन्होंने शहरी विकास, परिवहन और सड़क निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिससे उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना मजबूत हुई।

राजनीतिक दृष्टि से अखिलेश यादव का नेतृत्व आधुनिक सोच और युवा ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक छवि को बदलकर उसे विकास और प्रगतिशील राजनीति की ओर मोड़ा। हालांकि, उनका कार्यकाल पूरी तरह विवादों से मुक्त नहीं रहा। कानून व्यवस्था और कई मामलों में विपक्ष ने उनकी सरकार की आलोचना भी की। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। इसके बाद पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2017 के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कई रणनीतियां अपनाईं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया, हालांकि अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन राजनीति और किसान, युवा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को चुनावी केंद्र में रखा। यद्यपि पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर भी वे मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे। अखिलेश यादव को खेलों और पर्यावरण संरक्षण से विशेष लगाव है। फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है। वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच 'भैया' के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो उनके सरल और मिलनसार व्यक्तित्व को दर्शाता है। आज अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के प्रमुख चेहरा हैं। उनका सपना उत्तर प्रदेश को प्रगतिशील, आधुनिक और विकसित राज्य बनाने का है। वे युवाओं में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी सशक्त भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है। उनके राजनीतिक सफर और व्यक्तित्व से यह स्पष्ट होता है कि वे जमीनी राजनीति, सामाजिक न्याय, और विकास को समान महत्व देने वाले नेता हैं, जो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति में और भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

कमलनाथ की राजनीतिक समझ, निर्णय क्षमता और विकास का दृष्टिकोण कांग्रेस को मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है

(पेज 1 का शेष)

2023 में कांग्रेस को भले ही झटका लगा हो, लेकिन प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस की नीति और कमलनाथ की कार्यशैली आज भी प्रभावशाली मानी जाती है। अगर कांग्रेस नेतृत्व अनुभव और युवाओं के बीच सही तालमेल बैठा पाए तो 2028 के चुनाव में वह एक बार फिर सत्ता के समीकरण बदल सकती है। कमलनाथ की राजनीतिक समझ, उनकी निर्णय क्षमता और विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण आज भी कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। अब यह कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वे इस विरासत को किस प्रकार आगे ले जाते हैं।

कमलनाथ सरकार की योजनाओं को भुना रही बीजेपी सरकार

सियासी गलियारों में आज भी यह चर्चा आम है कि भले ही वर्तमान में डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हों, लेकिन उनके द्वारा लिए जा रहे कई फैसलों की जड़ें कमलनाथ की पिछली सरकार के नवाचारों और विकास नीति में ही छिपी हैं। कमलनाथ को भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठनात्मक मजबूती और नेतृत्व कौशल दोनों में सिद्धहस्त हैं। 2018 में जब उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी, तो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए कई साहसिक फैसले लिए। चाहे वह किसानों की कर्जमाफी हो, उद्योगों को आकर्षित करने के लिए निवेश सम्मेलन हों या शहरी विकास के लिए नई योजनाएं, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण, भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट- हर स्तर पर कमलनाथ ने प्रदेश को प्रगतिशील दिशा देने की कोशिश की। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि वे संगठन के सभी नेताओं को साथ लेकर चलते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस में गुटबाजी के बावजूद कमलनाथ को एक सर्वमान्य नेता माना जाता है। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते हुए युवाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखना और निर्णय प्रक्रिया में सामूहिकता लाना उनके नेतृत्व की पहचान रही है।

राजनीति में श्रेय की लड़ाई नई नहीं है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं जैसे 'एक जिला-एक उत्पाद', 'इंडस्ट्रियल कॉरिडोर' और 'नवाचार आधारित कृषि मॉडल'– अब भाजपा सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन्हीं योजनाओं को नए नाम और ढांचे में आगे बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कमलनाथ के विकास मॉडल ने प्रदेश में एक नई सोच की नींव रखी थी, जिसे भाजपा अब विस्तार दे रही है। मसलन, कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू किए गए 'शहरी रोजगार गारंटी' कार्यक्रम को अब 'मुख्यमंत्री रोजगार योजना' के नाम से पुनः प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय प्रबंधन में लाए गए बदलावों की बुनियाद आज भी पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में ही रखी गई थी।

2028 के चुनाव की तैयारी में अनुभव और युवा का तालमेल ही रास्ता

कांग्रेस के सामने अब 2028 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा लक्ष्य है। अगर पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है, तो उसे अनुभव और युवाओं के तालमेल को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। कमलनाथ जैसे अनुभवी नेता के मार्गदर्शन में कांग्रेस यदि युवा नेतृत्व को सशक्त करती है और संगठनात्मक ढांचे को जिला और बूथ स्तर तक मजबूत करती है तो वह भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनता अब केवल नारों और वादों पर नहीं, बल्कि नेतृत्व की स्पष्टता और नीति के धरातल पर वोट करती है। कांग्रेस को चाहिए कि वह कमलनाथ के कार्यकाल की उपलब्धियों को सही तरीके से जनता के बीच ले जाए और यह बताने में सफल हो कि भाजपा जो आज कर रही है, उसकी योजना असल में कांग्रेस ने बनाई थी।

आज मध्यप्रदेश में संगठन स्तर पर कांग्रेस की दशा दिखाई दे रही है उसमें एकता और समरूपता नही है। सरकार के विरोध में खड़ा दिखाई नहीं देता। वर्तमान में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को दमदार तरीके से घेरा जा सकता है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनकी टीम कोई ऐसा बड़ा आंदोलन ही नहीं कर पा रहे हैं जिससे सरकार सकते में आ सके।

कमलनाथ की राजनीतिक शैली, दूरदर्शिता और नवाचार

कमलनाथ के नेतृत्व की एक और विशेषता रही है– दृष्टिकोण में स्थायित्व और कार्यों में नवीनता। उन्होंने केवल राजनीतिक निर्णय ही नहीं लिए, बल्कि प्रशासनिक सुधारों की भी नींव रखी। उदाहरण के लिए, उनकी सरकार ने 'राइट टू वॉटर' जैसी योजना पर काम शुरू किया था, जो हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना थी। इस विचार को भाजपा सरकार अब 'हर घर नल' योजना के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में यह भी दिखाया कि वे केवल राजधानी केन्द्रित नहीं, बल्कि गांव और कस्बों की जरूरतों को समझने वाले नेता हैं। उनकी ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना, कृषि यंत्रीकरण नीति और स्थानीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजनाएं इसका प्रमाण हैं।

कांग्रेस के लिए रणनीतिक दिशा क्या हो सकती है?

जनता के बीच सही संदेश पहुंचाना- कांग्रेस को कमलनाथ की नीतियों और उपलब्धियों को सही परिप्रेक्ष्य में जनता के बीच पहुंचाना होगा। सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से यह बताना कि जिन योजनाओं पर आज भाजपा काम कर रही है, वे असल में कांग्रेस की सोच का परिणाम थीं।

नीतिगत स्पष्टता और संगठित कार्यशैली- संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूती देने और नीति निर्माण में सभी नेताओं की सहभागिता जरूरी है। कमलनाथ की संगठनात्मक समझ इस दिशा में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

राष्ट्रपति चुनाव में जिस उद्योगपति एलन मस्क ने ट्रंप की मदद की उसके ही खिलाफ खड़े हो गये ट्रंप

ट्रंप और मस्क के बीच उठते विवाद का कारण कहीं प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति तो नहीं?

-विजया पाठक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि विवादों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही दोस्त और उद्योगपति एलन मस्क से विवाद आरंभ कर दिया। अपने विवादित बयानों के लिये विशिष्ट पहचान रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर बैठते ही सबसे पहले भारत, फिर चीन और अन्य देशों को टारगेट किया और सभी पर जरूरत से ज्यादा टैरिफ लगाने का फैसला किया। खास बात यह रही कि भारत ने अपने कूटनीतिक रवैये से तो ट्रंप को टैरिफ लगाने के निर्णय से पीछे हटने को मना कर दिया, लेकिन चीन के साथ ट्रंप किसी भी तरह से टैरिफ हटाने को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं। बढ़ते दबाव और राजनीतिक खींचतान के कारण ट्रंप ने फिलहाल चीन पर लगाने वाले 154 प्रतिशत टैरिफ को तीन माह के लिये रोक दिया है। इस बीच ट्रंप के दोस्त और चुनाव में उनकी आर्थिक मदद करने वाले उद्योगपति एलन मस्क से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपने जिगरी दोस्त मस्क से दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और ट्रंप के बीच तनाव खुलकर सामने आ चुका है। हालात ये हैं कि दोनों ही दिग्गज सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ धमकियों में भी उलझ गए हैं।

इसलिये हुआ दोनों के बीच झगड़ा

ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप का ऐसा रवैया सामने आया है। इससे पहले भारत के साथ भी यूएस राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा ही किया। राष्ट्रपति के तौर पर पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप की पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती नजर आई। हालांकि, इस बार ट्रेड डील हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का मामला, यूएस राष्ट्रपति अलग राह पकड़े ही नजर आए। भले ही उन्होंने भारत के साथ 'दुश्मनी' वाला दांव चला हो लेकिन 'दोस्त' मस्क के साथ हुआ खेल, उनके लिए उल्टा जरूर पड़ गया है।

विवाद के बाद उठने लगे सवाल

डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो दोस्ती तो जल्दी करते हैं, लेकिन निभाते उसी से हैं जो उनकी शर्तों पर चले। ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अपने फैसलों से कई साथियों को चौंकाया। उन्होंने उन देशों से हाथ मिलाया जिनसे अमेरिका पहले दूरी रखता था। ट्रंप के बदले दांव से धीरे-धीरे उनके पुराने 'दोस्त' जैसे पीएम मोदी, पुतिन के बाद अब एलन मस्क उनसे दूर हो रहे हैं।

मस्क और ट्रंप के झगड़े के पीछे मोदी की कूटनीति तो नहीं

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप और मस्क के पीछे बढ़ते विवाद का एक कारण भारत भी हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिका के दौरे के दौरान मस्क से मुलाकात कर उन्हें भारत में टेस्ला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद मस्क भी इस विषय पर काफी एक्टिव हुए और उन्होंने मुंबई में लगभग 24 हजार वर्गफीट जगह पर अपना मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट आरंभ करने का निर्णय मोदी सरकार को भेज दिया है। ऐसे में ट्रंप को इस बात का भय है कि कहीं मोदी अपने कूटनीति से मस्क को उनके विपक्ष में न खड़ा कर दे जिससे आने वाले समय में उन्हें बड़ा नुकसान हो जाये। जाहिर है कि मोदी और बाइडेन की दोस्ती को लेकर दुनिया जानती है और यह भी लोगों को आशंका है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फिलहाल दोस्ती खटास में जाती दिखाई दे रही है।

इसलिये बदलने लगे ट्रंप के तेवर

विशेषज्ञ भी ट्रंप के बदले तेवर और नीतियों को समझने की कोशिश कर रहे। विश्लेषकों की मानें तो मौजूदा यूएस राष्ट्रपति की विदेश नीति किसी एक विचार से ज्यादा डील्स पर चलती है। उन्हें जहां फायदा दिखता है, वो वहीं चले जाते हैं। भले ही इससे उनका कोई करीबी दोस्त दूर हो जाए। इसका ताजा उदाहरण एलन मस्क के रूप में सबके सामने है। ट्रंप के साथ मस्क का विवाद यूएस प्रेसीडेंट की नई नीति 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' से शुरू हुआ।

मस्क ने उठा दिए ट्रंप की नीतियों पर सवाल

एलन मस्क ने ट्रंप की नई नीति 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' की आलोचना की। यह बिल टैक्स कटौती को बढ़ाने और अन्य संघीय कार्यक्रमों के लिए फंड बढ़ाने से जुड़ा है। मस्क ने ट्रंप की इस नीति पर सवाल उठाए। इसे अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लिए खराब बताया। इस आलोचना से नाराज होकर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मस्क को 'पागल' तक कह दिया और टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी उनकी कंपनियों के साथ सरकारी अनुबंध खत्म करने की धमकी दी।

यूएस अंतरिक्ष कार्यक्रम पर पड़ सकता है असर

ट्रंप ने लिखा कि मैंने एलन की बहुत मदद की, लेकिन अब वह मेरे खिलाफ हो गए हैं। सरकारी अनुबंध खत्म करके अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों और अन्य वस्तुओं को ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अंतरिक्ष कैप्सूल की सेवाएं निलंबित करने की धमकी दे दी। अगर स्पेसएक्स ऐसा करता है तो इससे नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि स्पेसएक्स के पास नासा के साथ अरबों डॉलर के अनुबंध हैं।

अब मस्क ने फोड़ दिया ट्रंप पर बड़ा बम

एलन मस्क यहीं नहीं रूके उन्होंने यूएस राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने लिखा कि 'अब समय आ गया है बड़ा बम फोड़ने का। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपस्टीन फाइल्स में है। यही कारण है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया।' एलन मस्क ने एक और पोस्ट में कहा कि 'इसे भविष्य के लिए मार्क कर लें। सच्चाई सामने आएगी।' यही नहीं मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने और उनकी जगह जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग वाली एक पोस्ट को भी शेयर किया।

पीएम मोदी से दोस्ती के बाद ट्रंप ने बदले तेवर

मस्क ही नहीं इससे पहले ट्रंप ने भारत के साथ भी धोखा किया। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छी दोस्ती कई बार देखी गई। 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' जैसे कार्यक्रमों में दोनों नेता 'दोस्त' की तरह नजर आए। हालांकि, जब ट्रंप को दोस्ती निभाने का मौका मिला, तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का साथ दिया। ट्रेड पॉलिसी में भी ट्रंप ने भारत को चुनौती दी। ट्रंप के तेवर भांपते ही केंद्र सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर लगाया। इसके साथ ही पुराने दोस्त रूस के साथ मेलजोल बढ़ाकर अमेरिका को करारा जवाब दे दिया।

आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप?

एलन मस्क, पीएम मोदी ही नहीं ट्रंप ने खेला रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी किया। पुतिन से दोस्ती के समय उन्होंने जेलेंस्की को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि, पुतिन से नाराजगी के बाद वे जेलेंस्की पर फिर मेहरबान हो गए। जानकारों के मुताबिक, ट्रंप की विदेश नीति में कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। उनकी नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, बल्कि डील्स पर आधारित होती है। ट्रंप को जहां फायदा दिखता है, वो वहीं चले जाते हैं। लेकिन इससे उनके करीबी 'दोस्त' छिटकते दिख रहे। जैसा कि मस्क के मामले में नजर आ रहा, जिनसे टकराव मोल लेना ट्रंप के लिए तगड़े झटके से कम नजर नहीं आ रहा।

भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा निकाली गई

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। देवरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। सुबह 9 बजकर 30 मिनट से भगवान को रथ पर बिठाने की धार्मिक विधियां की गई, इसके बाद लगभग 12 बजे भगवान को रथ पर विराजमान करवाया गया। देवरी में भव्यता एवं दिव्यता के साथ जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा गहोई वैश्य समाज द्वारा निकाली गई। कतकया मंदिर से यह यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के महिलाएं पुरुष एवं बच्चे भी शामिल हुए। जगह- जगह स्वागत

सत्कार किया गया। श्री हरि प्रभात फेरी के सदस्य भी शामिल हुए। गौरतलब है कि भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का शुभारंभ शुक्रवार से शुरु हो गया है। इस धार्मिक यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडिचा के मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों भक्त जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। आपको बता दें कि 27 जून से यह यात्रा शुरू हुई और 8 जुलाई को नीलाद्रि विजय के साथ इसका समापन होगा। इस दिन भगवान अपने धाम में वापस लौट जाएंगे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। यात्रा के दौरान गहोई वैश्य समाज के अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, संजय बृजपुरिया, अजय नगरिया, नपा अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन, पूर्व पार्षद रीना मनीष बडेरिया, पत्रकार संजय गुप्ता, अभितेन्द्र डब्बी मिश्रा, अमित कटारे, अशोक गुप्ता, माधव कनकने, लक्ष्मीनारायण बडेरिया, निक्की बृजपुरिया, पारस बृजपुरिया, आशीष रावत, संदीप बडेरिया, महेंद्र बडेरिया, राजा रेजा, टिंकु बृजपुरिया, राजा गुप्ता, बब्लू नगरिया, मुकेश नगरिया, नयन नगरिया, ओमकार विस्वकर्मा, कुलदीप नामदेव, सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के महिलाएं पुरुष एवं बच्चे भी शामिल हुए।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

प्रकृति की गोद में सेहत से संवाद

पिछले सात दिन मैंने पुणे के पास स्थित प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में बिताए। यह अनुभव सिर्फ एक अवकाश नहीं था, बल्कि मेरे शरीर, मन और आत्मा के लिए एक गहन जागृति थी। पहाड़ी से घिरे इस शांत और हरे-भरे परिवेश ने मुझे तुरंत अपने भीतर की शांति से जोड़ दिया। मूलशी झील के किनारे, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच आत्मंथन केंद्र की ताजी हवा और उच्च-ऊर्जा वाला वातावरण तनाव को तुरंत दूर कर देता है। एक सप्ताह बाद, मैं खुद के एक नए, अधिक ऊर्जावान और शांत स्वरूप को महसूस कर पा रहा हूँ। यह अनुभव किसी लक्जरी वेकेशन से बढ़कर, स्वास्थ्य के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता और आत्म-खोज का सफर था, जिसमें मैंने अपनी सेहत से संवाद किया।

प्राकृतिक चिकित्साः शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर की जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव, थकान, पाचन संबंधी समस्याएं और अनिद्रा जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। ऐसे में, प्राकृतिक चिकित्सा (नेचुरोपैथी) एक वरदान साबित होती है। यह कोई शौक या विलासिता नहीं, बल्कि "अंतर्मुखी जागरूकता की अनिवार्यता" है। यह पद्धति प्रकृति के पाँच तत्वों – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश – का उपयोग करके शरीर की स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता को जगाती है।

मेरे अनुभव में, प्राकृतिक चिकित्सा ने मुझे सिखाया

हाइड्रोथेरेपी (जल चिकित्सा): शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर ऊर्जा और ताजगी प्रदान करती है।

मिट्टी चिकित्सा: त्वचा और पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करती है, शरीर को ठंडक पहुंचाती है।

सूर्य स्नान: प्राकृतिक रूप से विटामिन डी के स्तर को संतुलित करता है और मन को शांत करता है।

प्राणायाम और ध्यान: मानसिक स्पष्टता लाते हैं, तनाव कम करते हैं और श्वसन क्षमता में सुधार करते हैं।

आयुर्वेद और योग: प्राचीन ज्ञान का आधुनिक उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, आयुर्वेद और योग ने मेरे अनुभव को और भी समृद्ध बनाया। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों साल पहले था।

आयुर्वेदः जीवन का विज्ञान

आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। इसने मुझे अपनी व्यक्तिगत प्रकृति (दोष- वात, पित्त, कफ) को समझने में मदद की। मुझे पता चला कि मेरी प्रकृति के अनुसार कौन-सा आहार और जीवनशैली मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। यह ज्ञान शरीर की जरूरतों को समझने और उसके अनुसार सही चुनाव करने में सहायक है।

योगः शारीरिक और मानसिक संतुलन का आधार

योग ने मेरे शरीर में अद्भुत लचीलापन और मानसिक एकाग्रता बढ़ाई। विभिन्न आसनों जैसे सूर्य नमस्कार ने पूरे शरीर को सक्रिय किया, जबकि शवासन ने गहन विश्राम प्रदान किया। प्राणायाम (श्वास-नियंत्रण) ने मेरे फेफड़ों को मजबूत किया और मन को शांत किया, जिससे विचारों में स्पष्टता आई। प्रकृति के हरे-भरे वातावरण में योग का अभ्यास करना किसी ध्यान से कम नहीं था, जिसने मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया।

स्वास्थ्य ही वास्तविक संपतिः घर पर करें शुरुआत, केंद्र पर करें विस्तार

मेरा यह अनुभव एक स्पष्ट संदेश देता है: स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, और यह कोई शौक नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं, जीवन की कोई भी उपलब्धि हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के सभी उपाय दिए हैं– हमें बस उन्हें अपनाने की आवश्यकता है।

आपके लिए एक्शन प्लानः घर पर कैसे करें शुरुआत?

सुबह की दिनचर्या में बदलाव

जल्दी उठें: प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें।

गुनगुना पानी: सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, यह शरीर की सफाई में मदद करता है।

हल्का व्यायाम: रोजाना 15-30 मिनट योग, प्राणायाम या तेज सैर करें।

धूप स्नान: रोजाना 10-15 मिनट सुबह की हल्की धूप लें, यह विटामिन डी के लिए आवश्यक है।

चबा-चबा कर खाएं: भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले या सोने से 2-3 घंटे पहले करें।

प्राकृतिक भोजन: बाजार के खाद्य पदार्थों, अतिरिक्त चीनी और जंक फूड से बचें। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज को प्राथमिकता दें।

ध्यान/प्राणायाम: रोजाना 10-15 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें।

प्रकृति से जुड़ें: आस-पास के पार्कों या हरियाली वाली जगह पर समय बिताएं।

यदि संभव हो, तो साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए गहन आयुर्वेदिक पंचकर्म या नेचुरोपैथी कार्यक्रम में भाग लें। यह शरीर की गहरी सफाई और पुनर्वास के लिए अत्यंत प्रभावी होता है।

स्वयं से जुड़िए, स्वस्थ रहिए

यह अनुभव मेरी तरफ से एक हार्दिक और अनुभव-सिद्ध सलाह है। हम अक्सर धन, पद और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे तो ये सब व्यर्थ हैं। मेरा मानना है कि "प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना ही सच्ची स्वस्थ जीवनशैली है।" आज ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का निर्णय लें। छोटी शुरुआत करें, लेकिन निरंतर बने रहें। प्रकृति आपको अवश्य पुरस्कृत करेगी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अपने शरीर से संवाद कीजिए, उसकी भाषा को समझिए, और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाइए।

युद्ध का पर्यावरण पर होता है खतरनाक असर

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

युद्धों की विभीषिका न केवल मानवीय त्रासदियों और आर्थिक तबाहियों के रूप में सामने आती है, बल्कि इनसे जो छिपा हुआ पर्यावरणीय विनाश दफ्तर में बैठी समझौतों की सुस्ती के बीच अनदेखा रह जाता है, वह कहीं अधिक खतरनाक है। रूस-यूक्रेन संघर्ष जहां सुदूर पूर्वी गाँवों से लेकर काला सागर तटीय इलाकों तक धुएँ की सतह फैला रहा है, वहीं इजराइल और ईरान की जमीन पर रात-दिन चल रहे हवाई हमलों ने हवा में मिट्टी के सूक्ष्म कण, धातु युक्त अवशेष और रासायनिक प्रदूषक अनगिनत घरों में प्रवेश करवा दिए हैं। यह प्रदूषण केवल सांस लेने में असुविधा भर नहीं बढ़ाता, बल्कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की अन्य पुरानी बीमारियों के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि भी ला रहा है। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयों के आँकड़े बताते हैं कि युद्ध-प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों में श्वसन संबंधी रोगी अक्सर दोगुने तक पहुँच जाते हैं। फिर भी यह क्षति वायु तक सीमित नहीं है। यमन के गृहयुद्ध में क्षतिग्रस्त तेल पाइपलाइनों से हुए गंदे तेल के रिसाव ने लाल सागर के तटीय जलमार्गों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे मछलियों, प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री जीवों में कुपोषण और जनसंख्या में गिरावट आई है। चार साल से अधिक समय से जारी संघर्ष के बीच, आसपास के गाँवों के मछुआरों ने लगभग 60% कम उपज दर्ज की है, जिससे उनकी आजीविका भी दाव पर है। सूदान में खार्तूम में जल आपूर्ति प्रणालियों का विनाश स्थानीय निवासियों को पीने के पानी के अभाव में तड़पने को मजबूर कर देता है, और इतना ही नहीं, टैंकों की भारी आवाजाही और बमबारी ने भूजल स्रोतों में विभिन्न भारी धातुओं और रसायनों का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है।

भूमि का दुष्प्रभाव युद्ध का एक और भयावह आयाम है। इथियोपिया के तिगरे क्षेत्र में बिखरे विस्फोटक अवशेष और जंग लगे कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक अनएक्सप्लोडेड बम-खांचा खेतों में दबे हुए हैं। ऐसे जहरीले अवशेष जमीन की उर्वरता को बर्बाद कर देते हैं और किसानों के लिए अपने खेतों में बीज बोने को जोखिमभरा बना देते हैं। अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में तो एक अनुमान के मुताबिक 10% कृषि योग्य जमीन आज भी माइन ब्लास्ट का खतरा लिए बैठे है, जिससे वर्षों पहले हुई लड़ाइयों का प्रभाव आज भी किसानों की पीठ पर बोझ बनकर टिका है। वन-क्षेत्र और जैव विविधता भी युद्ध में हुए जानलेवा हमलों से नहीं बच पाते। म्यांमार में चले गृहयुद्ध ने हजारों हेक्टेयर वर्षावनों को राख में तब्दील कर दिया था।। इन जंगलों में पनपने वाले दुर्लभ प्राणी जैसे इंडोचाइनीज टाइगर, एशियाई हाथी और पक्षियों की कई प्रजातियाँ आश्रय और भोजन के स्रोत खो बैठी हैं। फ़िलिपींस के दक्षिणी हिस्सों में विद्रोहियों और सेना के बीच जंगल कटाई ने केवल पेड़ों को नहीं काटा, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों की पारंपरिक जीवन-शैली और सांस्कृतिक विरासत को भी तार-तार कर दिया। युद्धों का गहरा असर जलवायु परिवर्तन पर भी दिखता है। भारी हथियारों की आवाजाही, टैंक और युद्धक वाहनों का लगातार परिचालन, विस्फोटक खाद्य-कअमोनियम के उच्च उत्सर्जन- ये सब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का भारी भार वायुमंडल में छोड़ते हैं। इस तथ्य को और गंभीर बनाता है कि अगर वर्तमान वैश्विक सैन्य गतिविधियों को एक राष्ट्र के शीतलन में रखा जाए, तो यह कार्बन उत्सर्जन के मामले में दुनिया के शीर्ष दस देशों में शुमार हो जाएगा। परमाणु अस्त्रों के संग्रह और तैनाती से उत्पन्न रेडिएशन रिसाव का खतरा तो और भी भयावह है: किसी एक बड़े परमाणु हमले के बाद 'न्यूक्लियर विंटर' जैसी स्थिति से विश्व का तापमान 5–10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे विश्वव्यापी कृषि अव्यवस्था और अभूतपूर्व भुखमरी की स्थिति बन सकती है।

युद्ध ने लोगों को उनके घरों से बेघर भी किया है, और इन विस्थापितों का दबाव नए रहने के स्थानों पर पर्यावरणीय संकट को और गहरा कर देता है। इतिहास गवाह है कि पहले विश्वयुद्ध और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भी लाखों एकड़ वन-क्षेत्र, नदी-तट और जमीन की सतह अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई थी। समय है आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि ठहर कर सोचने एवं ठोस कदम उठाने का है। युद्ध के पर्यावरणीय प्रभावों को रोकने के लिए एक वैश्विक संधि आवश्यक है, जिसमें 'पर्यावरणीय युद्ध अपराध' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में युद्ध की समाप्ति के बाद प्रभावी पुनर्वनीकरण (रीफॉरेस्टेशन) और भूमि पुनर्स्थापन अभियानों को अनिवार्य करना चाहिए। सैन्य उपकरणों में ग्रीन टेक्नोलॉजी का समावेश—जैसे इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन-चालित वाहनों का प्रयोग—कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। शांति समझौतों में खातावरणीय मुआवजा निधि की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि युद्धविराम के बाद नागरिक और प्रकृति दोनों को समान न्याय मिले। इस लेख का उद्देश्य केवल संबोधन करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार न सिर्फ इंसान, अपितु हमारी मातृभूमि और प्राकृतिक दुनिया भी है। अगर हमने आज नहीं सोचा, नहीं संवैधानिक स्तर पर विचार-विनिमय किया और नीतिगत सुधार नहीं किए, तो कल हमारे बच्चे और विश्व के सभी देशों के लोग भी इस विनाश के खंडहरों के बीच शांति की आस निहारते रह जाएंगे। समय है संभलने का, क्योंकि पृथ्वी को और इंसान को अब और प्रतीक्षा का अधिकार नहीं रहा।

छत्तीसगढ़

गढ़ रहा उद्योगों की स्थापना के नए अवसर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

"अब उद्यमी बनने की राह हुई आसान"

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0

- **पोर्टल के माध्यम** से 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा
- **उद्योगों की स्थापना** में सहयोग, युवाओं को रोजगार के मौके
- **ऑफलाइन मोड में** किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं
- पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का **क्लीयरेंस**
- **ई-चालान** के माध्यम से पेमेंट की सुविधा
- **सिंगल क्लिक पर** देखी जा सकती है आवेदन की स्थिति

R.O. No. :13313/1

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprog.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)